



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2019/आश्विन 2, 1941
No. 297]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019/ASVINA 2, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2019

(मामला सं. 06/2019)

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।

फा. सं. 7/15/2019-डीजीटीआर.—यतः मै. अजंता एल एल पी (जिसे पहले मै. अजंता प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था) (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटरों (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध किया गया है।

- और यतः आवेदक ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के समक्ष विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. के मूल की और वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाया है तथा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है

पृष्ठभूमि :

3. यतः चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना सं. 14/19/2013-डी जी ए डी दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 के द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 13 अप्रैल, 2015 की अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/19/2013-डी जी ए डी द्वारा चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। शुल्क को वित्त मंत्रालय द्वारा (एम ओ एफ) की शुल्क अधिसूचना सं. 24/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा लगाया गया था।

संबद्ध देश

4. वर्तमान जांच चीन जन गण से पी यू सी के कथित पाटन के संबंध में है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एक छोटा और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जिसका प्रयोग अंकगणित प्रचालनों और कतिपय अन्य गणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है। सरल संख्यात्मक प्रचालनों में मूलभूत अंकगणित जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग शामिल हैं, जटिल गणितीय कार्यों में एक्सपोनेंशियल प्रचालन, वर्गमूल, लागेरिथम, त्रिकोणमिती कार्य और हाइपरबोलिक कार्य आदि शामिल हैं और इसमें इसके सभी वाणिज्यिक/व्यापार शब्दावली वाले नाम शामिल हैं।
6. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर" हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं।
 - क. कैलकुलेटर जिनके साथ प्रिंटर लगा हो, जिन्हें आम तौर पर प्रिंटिंग कैलकुलेटर कहा जाता है।
 - ख. कैलकुलेटर जो चार्ट और ग्राफ बना सकते हों, जिन्हें आम तौर पर ग्राफिंग कैलकुलेटर का जाता है।
 - ग. प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर
7. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद मूल अधिसूचना में यथाअधिसूचित के समान रहेगा।
8. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद 8470 1000 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है।

समान वस्तु

9. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है :-
"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
10. आवेदक ने कहा है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और संबद्ध देशों से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर तकनीकी विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, वितरण एवं विपणन, कीमत निर्धारण और टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं।
11. विचाराधीन उत्पाद के दायरे को पूर्ववर्ती अंतिम जांच परिणाम के समय प्राधिकारी द्वारा विचारित दायरे के समान रखा गया है। आवेदक कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

12. यह आवेदन मै. अजंता एलएलपी द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने संबद्ध देश से न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पी यू सी के किसी

आयातक से संबंधित हैं। इसके अलावा, आवेदक का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक को घरेलू उद्योग माना है और वह नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंड को पूरा करते हैं।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

13. यतः पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार और विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

जांच की अवधि

14. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (जिसे आगे पीओआई कहा गया है) 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 (12 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में पिछले 3 वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

15. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में अधिसूचना सं. 14/19/2013-डीजीएडी दिनांक 13 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।
16. संबंधित नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।
18. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत की जा सकती है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

19. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
21. सभी हितवद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित 40 (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने

उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। सूचना मूल प्रतियों और सॉफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-
 - i. गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और
 - ii. अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।
23. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
24. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
28. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2019

(Case No. SSR 06/2019)**Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of Electronic Calculators ` originating in or exported from China PR.**

F. No. 7/15/2019-DGTR.—Whereas M/s. Ajanta LLP (formerly known as M/s. Ajanta Private Limited) (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”), for Sunset Review of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Electronic Calculators” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. AND WHEREAS, the applicant has filed a duly substantial application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating and exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject country.

Background

3. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from China PR was initiated by the Authority vide Initiation Notification No. 14/19/2013-DGAD dated 18th October 2013. The Authority vide its final finding notification No. 14/19/2013-DGAD dated 13th April 2015, recommended imposition of anti-dumping duty against imports of the subject goods from China PR. Duty was imposed by the Ministry of Finance (MoF) vide Customs Notification No. 24/2015- Customs (ADD) dated 29th May 2015.

Subject Country

4. The present investigation is in respect of alleged dumping of the PUC from China PR.

Product under consideration

5. The product under consideration in the present investigation is Electronic Calculators. An electronic calculator is a small and portable electronic device used for performing arithmetic operations and certain other mathematical functions. Simple numeric operations include basic arithmetic such as addition, subtraction, multiplication and division. Complex mathematical functions include exponential operations, roots, logarithms, trigonometric functions, and hyperbolic functions, etc. and include all its commercial/trade parlance names.
6. The product under consideration for the present investigation is ‘Electronic Calculators of all types’, *excluding* the following:
 - a. Calculators with attached printers, commonly referred to as *printing calculators*
 - b. Calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as *graphing calculators*
 - c. *Programmable calculators*
7. The present investigation being a Sunset Review Investigation, the product under consideration remains the same as notified in the original notification.
8. The product under consideration is classified under tariff item 8470 1000 of the Customs Tariff Act, 1975.

Like Article

9. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

10. The Applicant have submitted that the subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject country are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject country and those produced by the Applicant. Electronic Calculators produced by the Applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of technical characteristics, functions and uses, distribution and marketing, pricing and tariff classification. Consumers can use and are using the two interchangeably.
11. The scope of the product under consideration has been kept the same as was considered by the Authority at the time of previous final findings. Subject goods produced by the Applicant's company are being treated as "like article" to that being imported from the subject country for the purpose of the present review investigation.

Domestic industry & 'Standing'

12. The application has been filed by M/s. Ajanta LLP. The Applicant has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. Further, the Applicant accounts for a major proportion in Indian production of subject goods. Therefore, the Authority has considered the Applicant as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2 (b) and also satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules.

Initiation of Sunset Review

13. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset Review investigation to review the need for continued imposition of the duty in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Period of Investigation

14. The period of investigation (hereinafter referred to as "POI") for the present investigation is from 1st April 2018 to 31st March 2019 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the periods April 2015-March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.

Procedure

15. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/19/2013-DGAD dated 13th April 2015.
16. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of information

17. The known exporters in the subject country and their government through their embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001

19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

20. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's

application within forty days (40 days) from the date of the publication of this initiation notification. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

Submission of information on confidential basis

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
 - i. One set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. The other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in four (4) sets of each.
24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

29. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority